SDF–B–PBAD

लोक प्रशासन (प्रश्न-पत्र–II)

समय : तीन घण्टे

अधिकतम अंक : 250

प्रश्न-पत्र सम्बन्धी विशेष अनुदेश

(उत्तर देने के पूर्व निम्नलिखित निर्देशों को कृपया सावधानीपूर्वक पढ़ें)

इसमें **आठ** प्रश्न हैं जो दो खण्डों में विभाजित हैं तथा **हिन्दी** एवं **अंग्रेजी** दोनों में छपे हैं।

परीक्षार्थी को कुल **पाँच** प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

प्रश्न संख्या **1** और **5** अनिवार्य हैं तथा बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खण्ड से कम-से-कम **एक** प्रश्न चुनकर **तीन** प्रश्नों के उत्तर दें।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए, जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू० सी० ए०) पुस्तिका के मुखपृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द-सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।

प्रश्नों के उत्तरों की गणना क्रमानुसार की जाएगी। यदि काटा नहीं हो, तो प्रश्न के उत्तर की गणना की जाएगी चाहे वह उत्तर अंशतः दिया गया हो। प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

PUBLIC ADMINISTRATION (PAPER–II)

Time Allowed : Three Hours

Maximum Marks : 250

ABHYAS IAS ACADEMY Basics to Brilliance

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

(Please read each of the following instructions carefully before attempting questions)

There are EIGHT questions divided in two Sections and printed both in HINDI and in ENGLISH.

Candidate has to attempt FIVE questions in all.

Question Nos. **1** and **5** are compulsory and out of the remaining, THREE are to be attempted choosing at least ONE question from each Section.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Attempts of questions shall be counted in sequential order. Unless struck off, attempt of a question shall be counted even if attempted partly. Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

खण्ड—A / SECTION—A

1. निम्नलिखित में से प्रत्येक का लगभग *150* शब्दों में उत्तर दीजिए :

Answer the following in about *150* words each : 10×5=50

(a) *अर्थशास्त्र* के मूलपाठ में "राज्य न तो एक पुलिस राज्य है और न ही मात्र एक कर एकत्रित करने वाला राज्य है"। टिप्पणी कीजिए।

In the text of *Arthashastra*, "the State is neither a police State nor merely a tax gathering State". Comment.

(b) आर्थिक सुधारों ने भारत के संविधान के आधारभूत मूल्यों और आत्मा (भावना) का महत्त्वपूर्ण ढंग से अतिलंघन किया है। परीक्षण कीजिए।

The economic reforms have significantly infringed the basic values and spirit of the Indian Constitution. Examine.

(c) भारतीय सिविल सेवा पर मैकाले के विचार अधिकारीतंत्र की संभ्रांत थियोरी के समरूप हैं, जो अभी तक भी कायम हैं। क्या आप सहमत हैं? औचित्य सिद्ध कीजिए।

Macaulay's ideas on Indian Civil Service corresponded to the elite theory of bureaucracy, which continue to persist. Do you agree? Justify.

ABHYAS
IAS ACADEMY
Basics to Brilliance

(d) एक मत यह रहा है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था का विशिष्टाचार निरन्तर औपनिवेशिक बना हुआ है। त्वरित न्याय की प्राप्ति के लिए न्यायिक श्रेष्ठता के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए उपाय सुझाइए।

There has been an opinion that the ethos of Indian Judicial System continue to be colonial. Suggest measures for raising the level of judicial excellence for achieving speedy justice.

(e) विभिन्न आयोगों ने भारतीय शासन प्रणाली में राज्यपाल की निर्णायक भूमिका को बार-बार दोहराया है, किन्तु उत्तरोत्तर सरकारों ने राज्यपाल के पद को अराजनीतिक बनाने पर ध्यान नहीं दिया है। उदाहरणों सहित परीक्षण कीजिए।

Various commissions have reiterated the crucial role of the Governor in Indian system of governance, but the successive governments have not heeded to make the Governor's office apolitical. Examine with examples.

2. (a) अनुच्छेद 356 ''राज्य सरकार को उसकी न्यूनताओं को सुधारने का अवसर या नोटिस दिए बिना ... बहुत हद तक आसमान से बिजली गिरने जैसा काम करता है''। यह परिघटना न केवल राज्य सरकार की स्वायत्तता को क्षति पहुँचाती है, बल्कि भारत के राष्ट्रपति की प्रतिष्ठा को भी कम करती है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

Article 356 acts "very much like the proverbial bolt from the blue ... without giving an opportunity or notice to the State Government to correct its alleged shortcomings". This phenomenon not only undermines the autonomy of the State Government, but also demeans the status of the President of India. Critically analyze. 20

(b) सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों से अपेक्षा की गई थी कि वे भारतीय अर्थव्यवस्था को 'प्रभावशाली ऊँचाइयों' तक ले जाएँगे, इसके बजाय क्रमिक सरकारें इनको विनिवेश की ओर धकेलती रही हैं। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि विगत वर्षों में परिदृश्य कैसे-कैसे बदला है।

Public Sector Undertakings were expected to take the Indian economy to the 'commanding heights', instead the successive governments have been pushing for disinvestment. Critically examine how the scenario has changed over the years. 20

(c) समाज की उभरती हुई विकासीय आकांक्षाएँ लोक सेवकों को उपलब्ध वर्तमान सुरक्षा साधनों में परिवर्तन करने के लिए संविधान संशोधन को आवश्यक बनाती हैं। ऐसे संशोधन के पक्ष और विपक्ष में तर्कों का मूल्यांकन कीजिए।

ABHYAS
IAS ACADEMY
Basics to Brilliance

Emerging developmental aspirations of the society necessitate the constitutional amendment to change the present safeguards available to the civil servants. Evaluate the pros and cons of such amendment. 10

3. (a) ''शक्तिशाली प्रधानमंत्री कार्यालय (पी० एम० ओ०) मंत्रिपरिषद् के सामूहिक उत्तरदायित्व के लक्षण की विपरीतता है।'' इस कथन के प्रकाश में पी० एम० ओ० बनाम मंत्रिपरिषद् की पद-स्थिति से सम्बन्धित मुद्दों का परीक्षण कीजिए।

"Strong PMO is anti-thesis to the feature of collective responsibility of Council of Ministers." Examine the issues in relation to the position of PMO vis-á-vis Council of Ministers in the light of this statement. 20

(b) कर्मचारियों से सम्बन्धित क्षमता मुद्दों ने अनेक सरकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को बाधित किया है। राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति, 2012 के प्रावधानों के सन्दर्भ में, इसके कारणों का पता लगाइए।

Capacity issues relating to employees have hampered the implementation of several government programmes. Trace the reasons in the context of the provisions of the National Training Policy, 2012. 20

(c) हो सकता है कि बैंकों की गैर-निष्पादनी सम्पत्तियों से निपटने की रणनीति से करदाताओं पर अतिरिक्त भार पड़ जाय। इन दोनों के हितों की रक्षा के लिए सरकार की भूमिका का परीक्षण कीजिए।

The strategy to deal with the non-performing assets of banks may lead to overburdened taxpayers. Examine the role of government to protect the interests of both. 10

4. (a) केन्द्रीय और स्थानीय स्तरों के प्रशासन तंत्र की पुनर्रचना के बारे में पर्याप्त ध्यान दिया गया है, किन्तु राज्य स्तर पर बहुत ही कम सुधार किए गए हैं। इस स्थिति को सही करने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे?

Considerable attention has been paid to the restructuring of the administrative systems at the Central and local levels, but very few reforms have been undertaken at the State level. What steps would you suggest to rectify it? 20

(b) यह देखा जाता है कि जिला नियोजन समितियों की अकार्यशीलता ग्रामीण और नगरीय नियोजन की आवश्यकताओं की समानुरूपता को बाधित कर रही है। क्या आप सहमत हैं? औचित्य बताइए।

It is observed that non-functioning of District Planning Committees is preventing the convergence of rural and urban planning needs. Do you agree? Justify. 20

(c) पुलिस-जनता आमना-सामना (पारस्परिक सम्बन्धों) पर अविश्वास और डर के द्वारा विराम लग जाता है। सुझाइए कि जनता की नज़रों में पुलिस अपनी छवि को किस प्रकार सुधार सकती है।

The police-public interface is punctuated with distrust and fear. Suggest how the police can reform its image in the eyes of the public. 10

ABHYAS
IAS ACADEMY
Basics to Brilliance

खण्ड—B / SECTION—B

5. निम्नलिखित में से प्रत्येक का लगभग *150* शब्दों में उत्तर दीजिए :

Answer the following in about *150* words each : 10×5=50

(a) साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि विचार-विमर्शी लोकतंत्र का सपना तृणमूल स्तर पर व्यवहार में अर्जित नहीं किया जा सका है। ग्राम सभा के प्रकार्यकरण में बाधाओं का मूल्यांकन कीजिए।

The evidences suggest that the dream of deliberative democracy could not be realized in practice at the grassroot level. Evaluate the impediments in the functioning of Gram Sabha.

(b) ''सूचना के अधिकार ने अपनी यात्रा आरम्भ कर दी है, किन्तु यह अपनी मंजिल से बहुत दूर है।'' इस कथन की दृष्टि से सूचना का अधिकार आन्दोलन की वर्तमान स्थिति का परीक्षण कीजिए।

"The RTI has started its journey, but is far from its destination." In the view of the statement, examine the present status of the RTI movement.

(c) नव स्थानीयतावाद व्यवस्था की संकल्पना स्थानीय स्वशासन के मूल उद्देश्य को ही परास्त कर सकती है। क्या आप सहमत हैं? औचित्य सिद्ध कीजिए।

The concept of new localism arrangement may defeat the very purpose of local self-governance. Do you agree? Justify.

(d) अधिकारीतंत्र (नौकरशाही) में से 'अनुत्पादक लोगों को बाहर निकालने' के पहले प्रभावी 'निष्पादन प्रबन्धन तंत्र' की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए।

Effective 'Performance Management System' needs to precede 'taking deadwood out' from bureaucracy. Comment.

(e) सर्वमौसमी ग्रामीण संयोजकता योजना में असंयोजित ग्रामीण वासस्थानों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का रूपान्तरण करने की क्षमता है। क्या आप सहमत हैं? औचित्य सिद्ध कीजिए।

All weather rural connectivity scheme to even unconnected rural habitations has the potential to transform the rural economy. Do you agree? Justify.

ABHYAS
IAS ACADEMY
Basics to Brilliance

6. (a) ज़िला कलेक्टर का कार्यालय केवल सरकारी योजनाओं को पहुँचाने, आँकड़ों का संकलन करने और एक ऐसा अधिकारी बनकर रह गया है जो कभी न समाप्त होने वाली वी॰ आइ॰ पी॰ ड्यूटी में तैनात रहता है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के आलोक में इसकी भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

The office of the District Collector has merely become a bureau for funnelling government schemes, collecting statistics and an officer on attendance for unending VIP duties. Critically examine its role in the light of the recommendations of the Second Administrative Reforms Commission. 20

(b) राजनीतिक तंत्र में न्यूनतम जवाबदेही के प्रभावी मानक होते हुए, लोकपाल केवल सीमित प्रभाविता वाली एक आदर्श संस्था ही हो सकती है। समझाइए।

Minimal accountability being the dominant norm in the political system, the Lokpal can only be an ideal institution with limited effectiveness. Explain. 20

(c) 'सेवोत्तम योजना' की सेवा प्रदायगी में सुधार की अत्यधिक संभावना थी, परंतु अवसर को गँवा दिया गया है। टिप्पणी कीजिए।

'Sevottam Scheme' had great potential to reform service delivery, but opportunity is frittered away. Comment. 10

7. (a) आपदा प्रबन्धन की राष्ट्रीय नीति में अब तक की प्रतिक्रियात्मक आपदा-पश्चात् राहत केन्द्रिक व्यवस्था के स्थान पर अधिक अग्रलक्षी और समर्थक वातावरण की ओर आगे बढ़ने की परिकल्पना की गई है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की अनुक्रियाओं का परीक्षण कीजिए।

The National Policy on Disaster Management envisages a paradigm shift from hitherto reactive post-disaster relief centric regime to more pro-active and enabling environment. Examine the responses of State Governments in this regard. 20

(b) विगत वर्षों में राज्य वित्त आयोगों को सशक्त करने के प्रयासों को राज्य सरकारों की उदासीनता का सामना करना पड़ा है, जिसने क्रमिक केन्द्रीय वित्त आयोगों को भी स्थानीय निकायों को समुचित वित्तीय अंतरणों की सिफारिश करने में प्रभावित किया है। उत्तर को उदाहरणों सहित सिद्ध कीजिए।

Efforts to strengthen State Finance Commissions have faced apathy of State Governments over the years, which has also affected the successive Central Finance Commissions in recommending appropriate fiscal transfers to local bodies. Substantiate the answer with examples. 20

ABHYAS
IAS ACADEMY
Basics to Brilliance

(c) विनियामक निकायों की जवाबदेही, अति-विनियमन की समस्या को सुलझाने के साथ, उन्हें सच्चा सुकारक बनाने में सहायता करेगी। विनियामकों की वर्तमान प्रस्थिति का विश्लेषण करते हुए इस तंत्र में जवाबदेही उत्पन्न करने के उपाय सुझाइए।

Accountability of regulatory bodies would address the problem of over-regulation and help make them truly facilitators. Analyze the present status of regulators and suggest measures to induce accountability in the mechanism. 10

8. (a) भारत ने आर्थिक विकास के लिए जो रणनीति बनाई थी उसे 'नीति आयोग' ने बदल दिया है, किन्तु इसकी प्रभाविता को अभी देखा जाना शेष है, विशेष तौर से जब इसकी वित्तीय शक्तियाँ इसके पूर्ववर्ती की तुलना में बहुत कम हैं। विश्लेषण कीजिए।

'NITI Aayog' has changed the way India strategized for economic development, but its effectiveness is yet to be seen, especially when its financial powers are far less than its predecessor. Analyze. 20

(b) यद्यपि कानून और व्यवस्था प्रशासन एक राज्य विषय है, तथापि यह विरोधाभासी है कि संघ सरकार के अधीन केन्द्रीय अभिकरणों—एन० आइ० ए० या अर्द्धसैनिक बलों—ने राज्य सरकारों की शक्तियों को सीमित कर दिया है। विवेचना कीजिए।

Even though the law and order administration is a State subject, it is paradoxical that the Central agencies—NIA or paramilitary forces under the Union Government—have restricted the powers of State Governments. Discuss. 20

(c) भारत के वित्त आयोग द्वारा अवक्रमित (डिवोल्व्ड) निष्पादन अनुदानों ने स्थानीय निकायों की वित्तीय जवाबदेही में संवृद्धि कर दी है। विस्तार से समझाइए।

Performance grants devolved by Finance Commission of India have increased the financial accountability of the local bodies. Elaborate. 10

★ ★ ★

ABHYAS
IAS ACADEMY
Basics to Brilliance

ABHYAS
IAS ACADEMY
Basics to Brilliance